31. Shri Durga Cotton Spg. & Wvg. Mills Ltd., Konnagar (W. Bengal).

32. Kesoram Industries & Cotton Mills, Calcutta (W. Bengal).

33. Hada Textiles, Bishnupur (W. Bengal).

(b) Government have taken a number of steps to revitalise the Cotton Textile Industry. Important steps are:

(i) Augmentation of availability of raw materials and their equitable distribution.

(ii) Financially weak mills have been allowed exemption from production of controlled cloth.

(iii) A window has been opened in the I.D.B.I. for grant of soft loans to the cotton textile mills for the purpose of modernisation.

Since the N.T.C. is already shouldering an onerous responsibility of managing 105 sick cotton textile mills. Government do not favour taking over of more mills for management by the N.T.C. Selectively efforts are made however, to re-open closed mills which are basically viable, in consultation with the State Governments, representatives of the banks concerned and the labour. In a few cases where State Governments were willing to undertake financial and managerial responsibility, mills were taken over under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 for management by the State Government concerned.

कपड़ों पर लिखे गये माप

1957. **श्री रामानन्द तिवारी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अन्तर्गत चल रही कपड़ा मिलों द्वारा बनाये गये कपड़े के थान उन पर लिखे गये माप से कम पाये जाते हैं : और

(ख) क्या सरकार इस माप को ठीक कराने के लिए जांच करायेगी तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ।

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) और (ख). जी, नहीं । लूम शेड या परिष्करण विभाग से आने पर कपड़े की फोल्डिंग मशीनों पर तह की जाती है जो बिजली से चलती है । आमतौर पर फोल्डिंग मशीनों को एक-एक मीटर की तह करने के लिये उन्हें समन्वित किया जाता है और व्यापार प्रक्रिया तथा व्यापारियों की जरूरतों के अनुसार टकों / थानों की विभिन्न लम्बाई निश्चित की जाती है । वस्त्र नियंत्रण आदेश के अनुसार इन टकों / थानों पर लम्बाई के अनुसार मोहर लगाई जाती है । एक मीटर की मशीन से की गई तह का जब एक मीटर से मापा जाता है तो आमतौर पर इसमें कोई अन्तर नहीं पाया जाता है । तह को गलत तरीके से लगाने स लम्बाई नापने में कुछ अन्तर हो सकता है किन्तु, जब इस में किसी प्रकार के अन्तर का पता चलता है तो उसे ठीक करने के लिए तत्काल कार्रवाह की जाती है तथा टकों / थानों पर सही चिन्हांकन किया जाता है । इस प्रकार की मशीनी कमियां बहुत कम होती है । जब कभी इस प्रकार की गड़बड़ी का पता क्रेताओं को चलता है तो इस तथ्य को मिलों की जानकारी में लाया जाता है और उपयुक्त सुधारात्मक कार्यवाई की जाती है ।

Appointment of Civilian Teachers for Education Military Personnel

1958. SHRI NIRMAL CHANDRA JAIN: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether the civilian teachers appointed for imparting education to Military personnel etc., are required to work without having any chances of promotion;

(b) whether Government is also aware that the said fact hampers their efficiency; and

(c) whether Government propose to do something about the said teachers?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM): (a) to (c). Civilian Education Instructors in the Navy and Civilian School Masters in the Army are employed in lieu of combatants to teach Service personnel so long as combatant instructors are not available. In the Air Force, Civilian Education Instructors are employed on an adhoc basis under the Hindi Teaching Scheme to teach Hindi to Air Force personnel. At present, this is a temporary scheme.

All these teachers do not have any avenue of promotion in their own lines due to the circumstances of their employment. However, in the Army, Civilian School Masters are absorbed in the Clerical cadre, whenever vacancies arise, and are eligible, thereafter, for promotion to higher posts in that cadre. In the Navy, Civilian Education Instructors enjoy the same pay scale as that of trained graduate teachers of the Kendriya Vidyalayas.

राज्यों में पुलों का निर्माण और उन पर खर्च

1959. **श्री छबिराम अर्गल** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाले पुल के निर्माण कार्य के पूरा होने के बारे में 2 अप्रैल, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5674 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में मध्यप्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में आरम्भ किये गये अन्तर्राज्यीय पुलों के निर्माण के पूरा होने में कितना समय लगने की संभावना है ; और

(ख) उन पर अनुमानत: कितना खर्च होगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) :

(क) से (ख) : राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले निम्नलिखित अन्तर्राज्यीय पुल के निर्माण के लिए 20-1-1977 को 381 लाख रु० की केन्द्रीय ऋण सहायता स्वीकृत की गयी :-

क्र० सं०	पुल का नाम	केन्द्रीय ऋण सहायता की राशि	मिलाये जाने वाले राज्य	राज्य जो मुख्यत: निर्माण से संबंधित हैं
1	2	3	4	5
			(रु० लाखों में)	
1.	करोली-मंडरायल मुरैना सड़क पर चम्बल नदी पर पुल	65.00	राजस्थान तथा मध्य प्रदेश	राजस्थान